

भारत को दुनिया की टॉप-3 एआई सुपरपावर में से एक होना चाहिए

पीएम मोदी ने बताया 2047 का विजन

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एआई-इंडिया इम्पैक्ट समिट में भारत के आईटी क्षेत्र में एआई की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई भारत के आईटी सेक्टर को नष्ट नहीं कर रहा है, बल्कि इसे पूरी तरह से बदल रहा है। एआई को एक एनेबलर के रूप में देखा चाहिए, जो नई पीढ़ी की आउटसोर्सिंग और डोमेन-स्पेसिफिक ऑटोमेशन के माध्यम से विकास को बढ़ावा देगा। न्यूज एजेंसी ह्यू को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, एआई-संचालित बदलावों के कारण भारत का आईटी सेक्टर 2030 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह सेक्टर पहले से ही सेवाओं के निर्यात का मजबूत आधार रहा है। अब एआई के साथ यह उत्पादों, प्लेटफॉर्म और समाधानों के निर्माण में भी आगे जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को दुनिया की टॉप तीन एआई सुपरपावर में से एक होना चाहिए। सरकार ने इंडिया एआई

मिशन के माध्यम से मजबूत घरेलू एआई इकोसिस्टम विकसित करने की व्यापक रणनीति अपनाई है। इस मिशन के तहत तक की संख्या लक्ष्य से अधिक हो चुकी है और अब और 20,000 तक जोड़े जा रहे हैं, जिससे कुल 38,000 से अधिक हो जाएंगे। उच्च-स्तरीय तक अब मात्र 65 रुपये प्रति घंटे की दर से उपलब्ध हैं, जो वैश्विक औसत से लगभग एक-तिहाई कम है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और सस्टेनेबल सिटीज में चार सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस व रिकालिंग के लिए पांच नेशनल सेंटर्स स्थापित किए गए हैं।

भारत के पास क्या है टारगेट-प्रधानमंत्री ने कहा कि अगला चरण एआई के डिजाइन, रिसर्च और डेवलपमेंट पर केंद्रित होगा, ताकि भारत को जरूरतों के तहत समाधान तैयार हो सके। एआई से जुड़े निवेश 200 अरब डॉलर से अधिक होने की संभावना है। पीएम मोदी ने एआई में पूर्वाग्रह के मुद्दे पर भी गहन चिंता जताई और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एआई सिस्टम लिंग, भाषा और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े पूर्वाग्रहों

को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। पश्चिमी संदर्भों में वे बायस स्पष्ट नजर न आए, लेकिन भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता के कारण ये अलग-अलग तरीके से प्रकट हो सकते हैं। मुख्य रूप से अंग्रेजी या शहरी डेटा पर प्रशिक्षित एआई मॉडल ग्रामीण उपयोगकर्ताओं या क्षेत्रीय भाषाओं के बोलने वालों के लिए प्रभावी नहीं हो पाते।

मोदी बोले- भारत एवरेस्ट तक उड़ने वाला हेलिकॉप्टर बनाएगा, फ्रांस स्पेशल पार्टनर मैक्रों बोले- दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय



पीएम मोदी ने मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मुंबई में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मोदी ने कहा कि भारत और फ्रांस मिलकर भारत में ऐसे हेलिकॉप्टर का निर्माण करेंगे, जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भरेगा। मोदी ने फ्रांस को भारत का स्पेशल पार्टनर बताया और कहा कि दोनों देशों ने अपने रिसर्च को 'स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप' लेवल तक अपग्रेड करने का फैसला किया है। 'स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप' का मतलब है कि दोनों देश सिर्फ व्यापार या हथियारों की खरीद-फरोखत तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष, समुद्री इलाकों की सुरक्षा और बड़े वैश्विक मुद्दों पर साथ मिलकर काम करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच संबंध स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप लेवल के थे।

सुप्रीम कोर्ट बोला-नेताओं को भाषण से पहले विचार सुधारने की जरूरत

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस दौरान नेताओं और उच्च संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारियों को देश में भाईचारा बढ़ाने और संविधान के मूल्यों के हिसाब से व्यवहार करने और बोलने की नसीहत दी। भारत के चीफ जस्टिस सुर्यकांत, जस्टिस बी.वी. नागराज और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने कहा- नेताओं को देश में भाईचारा बढ़ाना होगा। नफरत भरे भाषणों को रोकने के लिए पहले सोच को सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि भाषण से पहले विचार आते हैं। सीजेआई ने कहा- सभी राजनीतिक दलों से हमारी अपील है कि आप संवैधानिक नैतिकता, मूल्यों, आपसी सम्मान और आत्मसम्मान के सिद्धांतों का पालन कीजिए। ये ठीक है कि आप वैचारिक सिद्धांतों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एकदूसरे का सम्मान करना भी जरूरी है। आप लोगों से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट नौ लोगों की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हालिया भाषणों और भाजपा असम की तरफ से पोस्ट किए गए एक वीडियो के महदेजर दावर की गई थी। वीडियो में एक खास समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगा था।

शिवराज सिंह ने राहुल को बताया पार्ट टाइम पॉलिटिशियन फुल टाइम ड्रामेबाज कहकर पूछे चार सवाल, 'भारत विस्तार' को बताया किसानों के लिए नई क्रांति

बढ़ता राजस्थान

जयपुर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ड्रामेबाज बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का काम झूठ बोलना और भ्रम फैलाना है, उन्हें ट्रेड, ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है।

शिवराज सिंह चौहान यह बयान जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान में 'भारत विस्तार' के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद में ऐसा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा गया, जो लोकतंत्र की मर्यादा तोड़कर केवल झूठ बोलें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार गलत जानकारी फैलाने का काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी से सवाल किया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एम्पएसपी तय करने का फैसला उनको सरकार ने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि उस समय यूपीए सरकार ने संसद में कहा था कि ऐसा करना संभव नहीं है, जबकि यह काम केवल नरेंद्र मोदी सरकार ने किया।

36 रुपए किलो चीनी आयात, 12 रुपए किलो पर निर्यात पर पूछा सवाल

उन्होंने कहा कि जब यूपीए सरकार के दौरान मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब रिकॉर्ड चीनी उत्पादन हुआ, लेकिन बफर स्टॉक नहीं बनाया गया।



आरोप लगाया कि उस समय 36 रुपए किलो चीनी आयात की गई और साढ़े 12 रुपए किलो के भाव पर निर्यात की गई, जिससे किसानों को नुकसान हुआ। इसी तरह 2009-10 में आटे और अनाज के निर्यात पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जब देश में महंगाई थी, तब अनाज विदेश क्यों भेजा गया।

अनाज सड़ने और गरीबों तक न पहुंचने का मुद्दा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय गोदामों में अनाज सड़ता रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी गरीबों को अनाज देने के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बाद में मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया।

व्यापार समझौतों पर दी सफाई

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अमेरिका और अन्य देशों के साथ हुए समझौते पूरी तरह भारत और किसानों के हित में हैं। गेहू, चावल और मक्का जैसे भरपूर अनाज के आयात की अनुमति नहीं दी गई है। सब आयात पर राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि भारत पहले से ही करीब 5 लाख मीट्रिक टन सब आयात करता है। अब अगर तुर्की की जगह अमेरिका से आयात होता है, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। न्यूनतम आयात मूल्य और शुल्क तय है।

जयपुर की प्रशंसा और किसानों पर जोर

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जयपुर शीर्ष, साहस, संस्कृति और कला का संगम है। भारत विस्तार जैसी किसान हितोपी तकनीक की शुरुआत जयपुर से होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि किसानों को आगे बढ़ाने के लिए खेतों और गांवों तक पहुंचना होगा।

ऑस्ट्रेलिया टी-20 वर्ल्डकप से बाहर, जिम्बाब्वे सुपर-8 में जिम्बाब्वे-आयरलैंड मैच बारिश से रद्द

बढ़ता राजस्थान



नई दिल्ली। 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग राउंड से ही बाहर हो गई है। मंगलवार को जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। केंडी के पल्लेकेले स्टेडियम में मैच का टॉस भी नहीं हो सका। इसी के साथ जिम्बाब्वे सुपर-8 में पहुंच गई है।

एक दिन पहले केंगारू श्रीलंका के खिलाफ 8 विकेट से हार गए थे। उन्हें 13 फरवरी को जिम्बाब्वे ने 23 रन से हराया था। अब ऑस्ट्रेलिया को 20 फरवरी को ओमान से खेलना है। इसे जीतकर भी मिचेल मार्श की टीम अगले दौर में नहीं पहुंच सकेगी।

ऑस्ट्रेलियन टीम इस टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरी बार ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। इससे पहले 2009 में टीम रिकी पॉटिंग की कप्तानी में लीग राउंड से बाहर हो गई थी।

गौहत्या पर विधानसभा में हंगामा, 7 बार कार्यवाही स्थगित

विधायक गोपाल शर्मा ने माफी मांगी, जूली बोले- कर्जा लेने में पांच साल का काम दो में किया

बढ़ता राजस्थान

जयपुर। विधानसभा में मंगलवार को जयपुर में गौहत्या और गाय को राज्यमाता का दर्जा देने से जुड़े सवाल के जवाब को लेकर 6 घंटे तक हंगामा हुआ। 7 बार सदन को कार्यवाही स्थगित हुई।

शाम 5.15 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि आज प्रश्नकाल के दौरान गाय को राज्यमाता से जुड़े सवाल पर जवाब के दौरान सदन में माहौल गरमाया। जयपुर में गौहत्या के मामले की जांच होनी चाहिए। प्रश्नकाल में जब यह मामला उठा उस वक्त भाजपा विधायक गोपाल शर्मा आवेश में आकर गुर्रसे में विपक्ष की तरफ आ गए थे। हम गोपाल शर्मा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देंगे।

सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गंग ने कहा कि कांग्रेस प्रेक्षाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इशारा करके गोपाल शर्मा को गौहत्या का हाथ, तब माहौल गरमाया था। गोपाल शर्मा पर विशेषाधिकार आगपा तो राजखेड़ा विधायक के खिलाफ भी आना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इसी बात को आगे बढ़ाया। हालांकि गोपाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी।

स्पीकर ने कहा- रिपोर्टिंग और कागज देखकर करेंगे फैसला

इस पूरे मामले में स्पीकर वासुदेव देवनानी ने आगे रिपोर्टिंग और दस्तावेज देखकर फैसला करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विधानसभा में गतिरोध खत्म हो गया। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भाषण शुरू हुआ। इसके बाद दिनभर चला गतिरोध शाम 5.15 बजे टूटा।

जूली बोले- आज तक ऐसा नौरस बजट कभी नहीं देखा

बजट बहस के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा- आज तक ऐसा नौरस बजट कभी नहीं देखा। बजट पेश करते चक कई मंत्री तो सदन में नौद



निकाल रहे थे। बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, लेकिन आपने तो थैले का रंग भगवा कर दिया।

जूली ने शायराना अंदाज में कहा- तुम सिफारिश से जहाँ पहुंचे हो, वहाँ हम चलकर आए हैं। वित्त मंत्री को बजट का थैला तो सुबह 9:30 बजे मिला था, ताकि अध्ययन नहीं कर सके। जूली ने बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली की लिंगभेदी टिप्पणियों पर तंज करते हुए कहा कि 16 फरवरी को आपके विधायक बजट पर बोलते हुए बेटा-बेटी में भेदभाव वाली बातें कर रहे थे। आपके विधायक हंस रहे थे। मुझे शर्म आती है, आज भी इस तरह की सोच रखते हैं। मेरे भी दो बेटियां हैं, एक बेटी को विदा करके आया हूँ। बेटियों के लिए भाजपा के विधायक इस जमाने में इस तरह की सोच रखते हैं।

जयपुर में गौहत्या पर जोरदार हंगामा

इससे पहले राजस्थान में गाय को राज्यमाता जयपुर में गौहत्या और गाय को राज्यमाता का दर्जा देने से जुड़े सवाल के जवाब को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। इस कारण विधानसभा की कार्यवाही प्रश्नकाल के बाद से 7 बार स्थगित हुई। दरअसल, बीजेपी विधायक बालमुकुंदचार्ज ने गाय को राज्यमाता का दर्जा देने और गोवंश तस्करी से जुड़ा सवाल पूछा था। जवाब में गोपालन मंत्री ने कहा कि गौहत्या रोकने कानून बना हुआ है। जूली ने कहा- राज्यमाता के दर्जे पर भी साफ जवाब नहीं दिया। इस बीच कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी।

दीया कुमारी ने राज्य कर्मचारियों को लेकर की बड़ी घोषणा...

अब वेतन-भत्तों की वसूली नहीं होगी, रिटायरमेंट तक इश्योरेंस कवर मिलेगा



विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कई घोषणाएं कीं। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग के दो साल की अवधि में केंद्र या राज्य की दूसरी नौकरी में चयन पर मौजूदा पद छोड़ने पर राहत देने की घोषणा की है। अब दो साल की ट्रेनिंग अवधि में पद छोड़ने पर वेतन भत्तों की वसूली नहीं होगी। साथ ही अब कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक इश्योरेंस कवर मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा- खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं, घाटे के बीच बोकलर हिसाब हमसे लेते हैं। हमारी सरकार राज्यस्व आय में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस सरकार के वक्त राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का के 4.4% था, जबकि हमारी सरकार की ओर से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 2025-26 में 3.87% अनुमानित किया। साल 2026-27 में कम करके 3.69% अनुमानित है।

हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली

विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए दीया कुमारी ने कहा- हमारी सरकार सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार है। विपक्ष की तथ्यात्मक आरोपना का हम स्वागत करते हैं। कुछ ने अनावश्यक अनागत आलोचना की, मैं आभारी हूँ कि उन्होंने कम से कम बजट तो पढ़ा। यह तो इनकी परंपरा रही है। बजट समझा भले न हो, लेकिन पढ़ तो लिया। नेता प्रतिपक्ष ने आज अनजाने ही सही हमारे पिछली बजट की तारीफ कर दी। आज उन्होंने कविताओं के अलावा ज्यादा कुछ आलोचना करने को मिला नहीं।

दीया कुमारी ने कहा- राजस्थान को पीछे किसने छोड़ा था, यह इतिहास जानता है। शिक्षा, कृषि पर नेता प्रतिपक्ष ने बजट कम करने की बात उठाई। हमारा कृषि बजट कांग्रेस सरकार से 34 प्रतिशत ज्यादा है।

Rajdhani Battery

Inverter • UPS • Battery

Deals in:

All Vehicle Battery, Inverter & Inverter Batteries & SMF Batteries

Mohd. Islam 9314625427

Mohd. Nasir 9982625427

Email: rajdhanibattery@gmail.com

Tonk Road, Near Gow Shala, Sanganer, Jaipur

सम्पादकीय

नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया आईना, सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने नेता एव वकील कपिल सिब्बल को उस याचिका को सुनने से मना कर सही किया, जिसमें असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के बयानों को आधार बनाकर हेत स्पीच यानी नफरती भाषण के खिलाफ कठोर दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इस याचिका में भाजपा के मुख्यमंत्रियों को निशाना बनाकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी कि केवल वही नफरती भाषण देने के आरोपित हैं। साफ है कि इस याचिका में बड़ी चतुराई से अन्य दलों के नेताओं के विषाक्त माने जाने वाले भाषणों का जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया। नफरती भाषण के खिलाफ दल विशेष के नेताओं को निशाना बनाने वाली इस याचिका ने यही बताया कि याचिकाकर्ता स्वयं दुराग्रह से प्रस्तुत है। देखा है कि वे संशोधित याचिका दायर करते हैं या नहीं और उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई दिशानिर्देश बनाता है या नहीं? वैसे यह आसान काम नहीं, क्योंकि नफरती भाषणों के खिलाफ प्रभावी गाइडलाइंस तभी बन सकती हैं, जब इसे परिभाषित किया जाए कि क्या नफरती है और क्या नहीं? इस संदर्भ में इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि कई बार किसी की ओर से कटु सत्य के उल्लेख को ट्रेष फैलाने वाला करार दिया जाता है तो कई बार नफरती भाषण को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आवरण पहनाने की कोशिश की जाती है। इस सबके बीच नेताओं की ओर से नफरती या फिर विभाजनकारी अथवा भड़काऊ भाषण दिए जाने का सिलसिला कायम है। नफरती भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के मामले दुर्लभ ही हैं। इसका कारण यह है कि जब कोई नेता ऐसे भाषण देता है तो उसके दल के लोग उसका बचाव करने के लिए आगे आ जाते हैं। यह भी देखा गया है कि राज्य सरकारें नफरती भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रायः पक्षपात करती हैं। कभी वे किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हैं तो कभी किसी के घोर आपत्तिजनक बयान की भी अनदेखी कर देती हैं। इस तरह का सबसे चकित करने वाला मामला तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि का है, जिन्होंने सनान धर्म को डेंगू, मलेरिया जैसा बताते हुए उसके खामे की बात की थी, पर राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया, क्योंकि वे मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भी अनदेखी की गई। अंततः न्यायपालिका के दखल के बाद ही उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सका। समस्या केवल यह नहीं कि संवैधानिक मूल्यों और सिद्धान्तों की अनदेखी के चलते राजनीतिक विमर्श विषाक्त होता जा रहा है और यही माहौल नफरती भाषणों का जरिया बन रहा है। समस्या यह भी है कि नियमन के अभाव में डिजिटल मीडिया में भी नफरती डिप्लिंग्या बेलगाम है। इससे भी सार्वजनिक विमर्श विषाक्त हो रहा है।

स्वयं सहायता समूह से सशक्तिकरण तक: बड़वा की जूती की गूँज देशभर में



डॉ. प्रियंका सौरभ

खंड कार्यक्रम प्रबंधक, सिवानी, जगबीर सिंह वर्मा ने बताया कि भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। सिवानी खंड में 402 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनसे लगभग 4000 महिलाएँ जुड़ी हैं। इन समूहों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, आर्थिक सहायता तथा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं।

हरियाणा की धरती परंपरा, परिश्रम और हुनर की अमोल्य विरासत से समृद्ध रही है। यहाँ के गाँव केवल कृषि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि हस्तकला और परंपरिक कौशल की जीवंत पहचान भी हैं। भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र के बड़वा गाँव की कारीगर कांता देवी ने इसी परंपरा को अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। आज उनकी बनाई हुई जूतियाँ गुर्राम में आयोजित सरस आजीविका मेले में ग्राहकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। यह सफलता केवल एक महिला को उपलब्धि नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता, महिला सशक्तिकरण और परंपरिक कला के पुनर्जागरण की प्रेरक कहानी है।



देवी ने लक्ष्मीबाई महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इस समूह के माध्यम से उन्होंने गाँव की अन्य महिलाओं को भी इस कार्य से जोड़ा। यह पहल केवल रोजगार का माध्यम नहीं बनी, बल्कि महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत उदाहरण भी बनी। इस समूह से जुड़कर महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता मिली और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। आज यह समूह कई महिलाओं के लिए स्थायी आय का स्रोत बन चुका है। समय के साथ कांता देवी ने अपने उत्पादों को एक नई पहचान देने के लिए 'अभिनिक इंडिया' नाम से अपना ब्रांड स्थापित किया। यह कदम उनके व्यवसाय के विस्तार में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस ब्रांड के माध्यम से उनकी जूतियाँ स्थानीय बाजार से निकलकर बड़े शहरों और राष्ट्रीय स्तर के मेलों तक पहुँचने लगीं। उनके बेटे ने ऑनलाइन विक्री की जिम्मेदारी संभाली, जिससे उनके उत्पाद डिजिटल प्लेटफॉर्म तक भी पहुँच गए। आज उनके पास 100 से अधिक डिजाइनों का संग्रह है, जो परंपरिक कला और आधुनिक फैशन का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। उनकी जूतियों की कीमत 350 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक है और उनका मासिक

कारोबार लगभग तीन लाख रुपये तक पहुँच चुका है। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि यदि ग्रामीण उत्पादों को सही मंच और अवसर मिले, तो वे आर्थिक रूप से अत्यंत सफल हो सकते हैं। यह सफलता केवल आर्थिक उपलब्धि नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और सम्मान की भी कहानी है। इस उपलब्धि में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस मिशन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और बाजार उपलब्ध कराया जाता है। इसी मंच के माध्यम से कांता देवी को सरस मेले में अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिला। सरस मेला ग्रामीण कारीगरों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ उन्हें अपने हुनर पर भी अपनी पहचान बना सकती है। कांता देवी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत संकल्प और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि व्यक्ति अपने कौशल पर विश्वास रखे और मेहनत करे, तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। आज कांता देवी केवल एक कारीगर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुकी हैं। उन्होंने यह दिखाया है कि परंपरिक कला केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का आधार भी है। उनके पति और ससुर के सहयोग से शुरू हुई यह यात्रा आज सामाजिक प्रभाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उनका सम्मान भी बढ़ता है। वे परिवार के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाएँ लगी हैं और अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने में योगदान देती हैं। कांता देवी की सफलता ने गाँव की अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया है कि वे अपने कौशल का उपयोग कर आत्मनिर्भर बन सकती हैं। यह सफलता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब गाँव में ही रोजगार उपलब्ध होता

पारदर्शिता की पहल, पर एकरूपता के अभाव में अदालतों तक पहुँचते कर्मचारी



डॉ. सत्यवान सौरभ

(सभी कर्मचारियों की एकमुश्त अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि कार्यस्थल वरिष्ठता निष्पक्ष रूप से निर्धारित हो और भविष्य में किसी प्रकार की असमानता या भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो। ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद पारंपरिक स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। सभी विभागों में समान कार्यकाल व्यवस्था लागू हो, जिससे कर्मचारियों को समान अवसर मिल सकें। नई नियुक्तियों को समयबद्ध रूप से ऑनलाइन प्रणाली में शामिल किया जाए, ताकि वरिष्ठता प्रभावित न हो। स्थानांतरण प्रक्रिया का निश्चित वार्षिक कार्यक्रम हो, जिससे पारदर्शिता बढ़े और कर्मचारियों में अनिश्चितता समाप्त हो।)

हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई आदर्श ऑनलाइन स्थानांतरण नीति प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण और साहसिक कदम है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर मनमानी, सिफारिश, पक्षपात और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती रही हैं। इन समस्याओं को समाप्त करने और प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष तथा योग्यता आधारित बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू की गई। इसका मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता, सेवा अवधि और विशेष परिस्थितियों के आधार पर न्यायपूर्ण तरीके से कार्यस्थल आवंटित किया जाए तथा किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो। यह नीति आधुनिक प्रशासनिक सोच और तकनीकी उपयोग का सकारात्मक उदाहरण है। 50 या उससे अधिक पदों वाले संगठनों पर लागू इस व्यवस्था में 80 अंकों का योग्यता आधारित मूल्यांकन तंत्र निर्धारित किया गया है। इसमें आयु और कुल सेवा अवधि को प्रमुख आधार बनाया गया है, जिससे वरिष्ठता को उचित महत्त्व मिल सके। सेवा अवधि को 365 दिनों से विभाजित कर अंक निर्धारित किए जाते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी बनती है। महिला कर्मचारियों को 10 अंक, पति-पत्नी मामलों में 5 अंक तथा गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के मामलों में 10 से 20 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं।

पुरी प्रक्रिया मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से जुड़े ऑनलाइन मंच के माध्यम से संचालित होती है। अधिसूचना जारी होने के बाद संवर्ग सूची सार्वजनिक की जाती है और कर्मचारी एकमुश्त पासवर्ड के माध्यम से सत्यापन कर अपने पसंदीदा कार्यस्थलों का चयन करते हैं। निर्धारित समय में विकल्प प्रस्तुत न करने की स्थिति में कर्मचारी को किसी भी स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है। अतिरिक्त पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाता है तथा आदेश जारी होने के निर्धारित समय के भीतर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक होता है। नीति लागू होने के बाद कई विभागों में पारदर्शिता बढ़ी है और शिकायतों में कमी भी आई है। ऑनलाइन अधिसूचना निवारण तंत्र ने कर्मचारियों को अपनी बात रखने का मंच दिया है। इससे यह विश्वास मजबूत



हुआ है कि अंकीय प्रणाली के माध्यम से प्रशासनिक सुधार प्रभावी रूप से लागू किए जा सकते हैं। फिर भी, नीति के क्रियान्वयन में एकरूपता का अभाव इसकी सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। सभी विभागों में समान कार्यकाल, समान समय-सारिणी और समान नियम लागू नहीं हैं। कहीं न्यूनतम कार्यकाल अलग है, कहीं अधिकतम कार्यकाल की सीमा भिन्न है, तो कहीं विशेष परिस्थितियों की परिभाषा बदल जाती है। इससे समान संवर्ग के कर्मचारियों के बीच असमानता उत्पन्न होती है और नीति की मूल भावना प्रभावित होती है। ऑनलाइन स्थानांतरण अभियान की पहली ही प्रक्रिया में सभी कर्मचारियों की एकमुश्त अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि प्रारंभिक चरण में कुछ कर्मचारी किसी कारणवश बाहर रह जाते हैं, तो उनकी कार्यस्थल वरिष्ठता प्रभावित होती है और भविष्य में विवाद की स्थिति बनती है। इसलिए 'एक बार की अनिवार्य सहभागिता' के माध्यम से सभी कर्मचारियों को समान आधार पर, तो लाना चाहिए। सभी विभागों में निर्धारित कार्यकाल समान होना चाहिए। उदाहरण के लिए न्यूनतम कार्यकाल एक वर्ष या एक स्थानांतरण अभियान से अगले अभियान तक तथा अधिकतम कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारित किया जा सकता है। इससे कोई भी कर्मचारी अत्यधिक लंबे समय तक एक ही स्थान पर नहीं रहेगा और न ही किसी को अल्प अवधि में बार-बार स्थानांतरण झेलना पड़ेगा। जब भी नई नियुक्तियाँ हों, उसे अनिवार्य रूप से अगले स्थानांतरण अभियान में शामिल किया जाना चाहिए। यदि ऑनलाइन स्थानांतरण नीति लागू होने के बाद अब तक कोई कर्मचारी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ है, तो उसे वर्तमान

अभियान में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए। इससे सभी कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्यस्थल प्राप्त करने का अवसर मिलेगा और मनमानी या रिश्तेदारी के माध्यम से पारंपरिक आदेशों द्वारा कार्यस्थल प्राप्त करने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। सभी विभागों में स्थानांतरण अभियान एक ही समय पर पूरा किया जाना चाहिए। इससे पति-पत्नी प्रकरणों में निर्णय लेने में सुविधा होगी और परिवारों को अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि विभिन्न विभाग अलग-अलग समय पर स्थानांतरण करेंगे, तो पारिवारिक समन्वय कठिन हो जाता है। कार्यकाल की गणना करते समय वित्तीय वर्ष को एक वर्ष माना जाना चाहिए, न कि दिनों की गणना के आधार पर। कई बार स्थानांतरण अभियान वित्तीय वर्ष के मध्य में पूरा होता है और कार्यभार ग्रहण वर्ष के अंतिम चरण में होता है, जिससे कार्यकाल की गणना में एक वर्ष का अंतर उत्पन्न हो जाता है। यदि वित्तीय वर्ष को पूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया जाए, तो कट-ऑफ तिथि से संबंधित विवाद समाप्त हो सकते हैं। हर वर्ष एक निश्चित और पूर्व घोषित समय-सारिणी के अनुसार स्थानांतरण अभियान चलाया जाना चाहिए। यदि यह प्रक्रिया नियमित और वार्षिक हो, तो कर्मचारियों में अनिश्चितता समाप्त होगी और प्रशासनिक समन्वय बेहतर होगा। अनियमित या विलंबित अभियान से भ्रम और असंतोष की स्थिति उत्पन्न होती है। पद पुनर्संरचना या युक्तिकरण की प्रक्रिया के दौरान, यदि अगली भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी हो, तो न्यूनतम पदों को अवरुद्ध किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को अपने निवास स्थान के निकट कार्यस्थल मिलने की अधिक संभावना रहे।

समृद्ध मध्य प्रदेश 2047: विकसित राज्य की अमृत काल उड़ान

मध्य प्रदेश को हम यदि पीछे मुड़कर देखें, तो 23 साल पहले (2003) तक देश का हृदय प्रदेश अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करता एक 'बीमारू' की श्रेणी में खड़ा था। वह एक ऐसा दौर था जब प्रदेश में सड़के उखड़ी पड़ी थी। पर्याप्त बिजली नहीं होने के कारण लोग रात-रात भर अंधेरे में गुजरने को मजबूर थे। पानी की कोई ठोस व्यवस्था सुनिश्चित नहीं थी। यहां तक कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए भी खजाने में जट्टीजहद करनी पड़ती थी। प्रशासनिक तंत्र में निराशा थी और जनमानस में अपनी नियति को लेकर संशय। तब प्रदेश के हर नागरिक के मन में एक सवाल उठता रहा होगा कि क्या मध्य प्रदेश इस दशा से कभी उभर भी पाएगा, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बदली और आज वही मध्य प्रदेश निराशा के उस दौर को पूरी तरह पीछे छोड़ 'समृद्ध मध्य प्रदेश 2047' के विजन के साथ एक ऊँची और महत्वाकांक्षी उड़ान भरने के लिए तैयार है।



डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार पिछले दो वर्षों से एक सुस्पष्ट कार्ययोजना और दूरदृष्टि के साथ इसी लक्ष्य को लेकर निरंतर आगे बढ़ रही है। इस विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि डॉ. यादव को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का जो सहयोग और मिल रहा है, वह विकास यात्रा की रफतार को नई ऊर्जा दे रहा है। प्रदेश के लिए यह वास्तव में वह 'अमृत काल' है, जहाँ हर नीति, हर योजना और हर सरकारी निर्णय का अंतिम ध्येय वर्ष 2047 तक राज्य को न केवल आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उसे देश के अग्रणी विकसित राज्यों की पंक्ति में प्रथम स्थान पर खड़ा करना है।

आर्थिक महाशक्ति और 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य

डॉ. मोहन यादव सरकार का सबसे प्रमुख संकल्प मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2 ट्रिलियन डॉलर के विराट लक्ष्य तक पहुँचाना है। यह प्रदेश के हर नागरिक की क्रय शक्ति और जीवन स्तर को वैश्विक मानकों तक ले जाने का रोडमैप है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2025 को 'उद्योग एवं रोजगार वर्ष' के रूप में मनाकर औद्योगिक निवेश के लिए द्वार पूरी तरह खोल दिए गए हैं। हालिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2025 और प्रदेश के विभिन्न अंचलों में आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनों के माध्यम से 11.09 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक निवेश प्रस्तावों का आना इस बात का साक्ष्य है कि मध्य प्रदेश अब वैश्विक निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है।

आज प्रदेश में 23 लाख से अधिक लघु उद्योगों की इकाइयों सवा करोड़ लोगों को रोजगार दे रही हैं। जिस प्रदेश में कभी उद्योगों के लिए बिजली का संकट था, आज वहाँ औद्योगिक अधोसंरचना इतनी सुदृढ़ है कि विश्वस्तरीय कंपनियों यहाँ अपने प्लांट स्थापित कर रही हैं। सबसे सुखद पहलू यह है कि नए स्टार्टअप में 47 प्रतिशत भागीदारी महिलाओं की है, जो एक आधुनिक और प्रगतिशील आर्थिक युग के सूत्रपात का उद्घोष है। सरकार की 'निर्गत संवर्धन नीति 2025' और 'लॉजिस्टिक नीति' ने प्रदेश के उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार के रास्ते खोल दिए हैं।

अनदाता की खुशहाली: कृषि से सहकारिता का नया युग

कृषि उत्पादन में देश का सिरमौर बना मध्य प्रदेश अब डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में खेती को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाने की दिशा में नए प्रयोग कर रहा है। कभी 'पानी की कमी' के लिए पहचाने जाने वाला यह राज्य आज सिंचाई के रकबे में देश के अग्रणी राज्यों में है। भावांतर भुगतान और मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना के माध्यम से सोयाबीन, धान और मूँग उत्पादकों के खातों में हजारों करोड़ रुपये का सीधा हस्तांतरण किया जा रहा है। रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना के जरिए कोटो-कूटकी जैसे पारंपरिक अनाजों को वैश्विक पहचान दिलाकर सरकार ने न केवल पोषण की दिशा में काम किया है, बल्कि जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी है। सहकारिता के क्षेत्र में सरकार का विजन बहुत स्पष्ट है, पैसस और डेलरी समितियों की संख्या को दोगुना करना। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा, जो आने वाले दशकों में प्रदेश की आय का मुख्य आधार बनेगी। 500 मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाली प्रत्येक प्राथमिक सहकारी समिति किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026: नवाचार से राष्ट्र निर्माण तक

परिवर्तन का सबसे प्रमुख उदाहरण बनकर उभरी है। तेजी से बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच दुनिया भर में आधुनिक तकनीकों के विकास और नवाचार पर विशेष जोर बढ़ा है। आज दुनिया के विभिन्न देश अपनी नीतियों में नई-नई तकनीकों व नवाचारों को शामिल कर अपने देश की विभिन्न पारंपरिक कार्यप्रणालियों को लगातार बदल रहे हैं। विशेष रूप से एआई ने वैश्विक स्तर पर कार्य प्रणाली और मानव भूमिका को गहराई से प्रभावित किया है, इसलिए आज इसे विकास के लिए अनिवार्य और बहुत ही अहम माना जा रहा है। इसी संदर्भ में, नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण एआई शिखर सम्मेलन (इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026; 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक) आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य एआई की संभावनाओं, इसकी चुनौतियों,

रोजगार पर इसका प्रभाव और आम जीवन में इसके उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। कदना गलत नहीं होगा कि आज एआई का दायरा स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, कारोबार और रक्षा जैसे क्षेत्रों तक फैल चुका है, जिससे नए अवसर पैदा हुए हैं, लेकिन यह भी कटु सत्य है कि रोजगार पर प्रभाव, जोखिम, डेटा सुरक्षा और पर्यावरणीय असर जैसे चिंताएँ भी इसके कारण सामने आई हैं। विशेष रूप से डेटा केंद्रों में ऊर्जा और पानी की बढ़ती खपत को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। इसलिए एआई आधारित विकास को सफल बनाने के लिए इसके लाभों के साथ-साथ संभावित खतरों के समाधान पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है।

बहरहाल, यहां पाठकों को बताता चूँ कि नई दिल्ली के भारत मंडप में 16 से 20 फरवरी 2026 तक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह पाँच दिवसीय कार्यक्रम ग्लोबल साउथ में आयोजित पहला प्रमुख एआई शिखर सम्मेलन माना जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं और एआई नीति तथा नवाचार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। गौरवलाभ है कि यह समिट भारत मंडप सहित नई दिल्ली के विभिन्न स्थलों पर आयोजित हो रही है तथा इसमें 100 से अधिक कंपनियों जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ), शोधकर्ता, नीति-निर्माता और कई देशों के राष्ट्रीय शक्ति शामिल हो रहे हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम के दौरान 500 से अधिक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि 800 से अधिक प्रदर्शक, स्टार्टअप, शोध संस्थान और

राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल इसमें भाग ले रहे हैं। 16-20 फरवरी तक आयोजित यह एआई शिखर सम्मेलन भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत कृषि बुद्धिमत्ता (एआइ) के क्षेत्र में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, जबकि उससे आगे केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्लोबल एआई वाइब्रेसी टूल के अनुसार भारत का स्कोर 21.59 है, जबकि अमेरिका का 78.6 और चीन का 36.95 है। इस सूचकांक में भारत कई विकसित देशों जैसे दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस से आगे है। भारत वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ-साथ एआई के क्षेत्र में अग्रणी विकासशील देश भी बन चुका है। इसलिए इस स्तर का वैश्विक आयोजन पहली

बार किसी विकासशील देश में होना ऐतिहासिक माना जा रहा है। सम्मेलन में 13 देशों के लगभग 300 पब्लिकन वाले एक्सपो का आयोजन भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के माध्यम से आम लोगों तक तकनीक के लाभ पहुँचाने, सस्ती तकनीक उपलब्ध कराने और वैश्विक असमानताओं को कम करने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, बशर्ते देश निवेश बढ़ाए, प्रतिभाओं को बनाए रखे और अनुकूल तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करे। वास्तव में, यह समागम विश्व के सबसे बड़े एआई आयोजनों में से एक माना जा रहा है और ग्लोबल साउथ में आयोजित पहली बड़ी एआई शिखर बैठक के रूप में देखा जा रहा है, जिससे भारत सहित विभिन्न विकासशील देशों की भूमिका अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेगी। सम्मेलन में एआई आधारित नवाचार, प्रतियोगिताएँ, हैकार्थन तथा करोड़ों रुपये के पुरस्कार वाले कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

पीड़ित और जरूरतमंद की सेवा ही ईश्वर की पूजा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है-सीताराम वैरवा



बढ़ता राजस्थान

डोंग (नि.स.)। अखिल भारतीय ब्राह्मण महा सभा एवं गांधी सर्वोदय संस्थान के द्वारा मंगलवार को शहर के श्री मोहनजी मंदिर में भाजपा नेता लखपत गुर्जर की अध्यक्षता में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें भामाशाह मोहन स्वरूप पाराशर और उमेश पाराशर के सौजन्य से सीओ सीता राम वैरवा के मुख्यातिथ्य में 101 जरूरत मंद विधवा महिलाओं को कंबल वितरित किए गए।

विशिष्ट अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनीता राघव, प्राचार्य गोपाल प्रसाद शर्मा, भाजपा नेता प्रदीप शर्मा शिक्षाविद कृष्ण बल्लभ शर्मा थे। मुख्य अतिथि सीओ वैरवा ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा ही ईश्वर की पूजा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है इसलिए प्रत्येक समर्थवान व्यक्ति को जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने समाजसेवी लोगों से भी ऐसे पुनीत कार्य में आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में लखपत सिंह गुर्जर और रोशनी चौधरी, शिक्षा के क्षेत्र में लक्ष्मण

पाराशर के पी सिंह तथा दसगं में अच्चे अंक लाने वाले विद्यार्थियों में देव मुद्रल, व्योम मुद्रल और कनिष्क मुद्रल को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन चंद्रभान चंद्र ने किया। इस अवसर पर सतीश दुबे, विष्णु शर्मा, लक्ष्मण सिंह, दीपचंद शर्मा, विनीता पचौरी, जगत पाराशर आदि मौजूद रहे।

राजपाल सिंह भाटी को मिला 'बेस्ट ट्रेफिक पुलिस अवार्ड', जयपुर कमिश्नरट में हुआ सम्मान



बढ़ता राजस्थान

पावटा (नि.स.)। उपखंड क्षेत्र के ग्राम दौलत निवासी राजपाल सिंह भाटी ने अपने उत्कृष्ट कार्य से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। जयपुर ट्रेफिक पुलिस में कार्यरत राजपाल सिंह भाटी को जयपुर पुलिस कमिश्नरट द्वारा आयोजित भव्य समारोह में 'बेस्ट ट्रेफिक पुलिस अवार्ड' से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने, नियमों के प्रभावी पालन तथा जनसेवा के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण के लिए प्रदान किया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें प्रशंसा पत्र और पदक प्रदान कर सम्मानित किया। समारोह में उपस्थित अधिकारियों और गणमान्यजनों ने उनके कार्य की भूरि-भूरि सराहना की। राजपाल सिंह भाटी अपने कर्तव्यनिष्ठ व्यवहार, अनुशासन और सकारात्मक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जयपुर की व्यस्त सड़कों पर यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के साथ-साथ आमजन में ट्रेफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। उनका योगदान सुरक्षित और सुव्यवस्थित जयपुर के निर्माण में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस उपलब्धि पर ग्राम दौलत सहित पूरे पावटा क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामवासियों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनके उज्वल भविष्य की कामना की है।

फाइनेंस ऑफिस पर दिन दहाड़े फायर करने वाले तीन बदमाश गिरफ्तार

- आरोपियों में एक अंतरराज्यीय बदमाश भी, जिस पर कई अन्य मामले भी दर्ज हैं

बढ़ता राजस्थान

सिरोही (नि.स.)। रेवदर कस्बे में दिन-दहाड़े फायर करने वाले तीन बदमाशों का गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। तीन दिन पहले ही बदमाश रेवदर कस्बे में एक फाइनेंस ऑफिस में बैठे कर्मचारी पर फायर कर फरार हुए थे। गिरफ्तार आरोपियों में एक अंतरराज्यीय बदमाश भी शामिल है, जिस पर कई राज्यों में विभिन्न मामलों दर्ज हैं।

पुलिस के अनुसार रेवदर में एक वाहन में आए बदमाशों ने एक फाइनेंस ऑफिस को टारगेट किया था। यहां सेट के बारे में जानकारी मांगी। इसके बाद बदमाशों ने वहां बैठे कर्मचारी पर दो राउंड फायर दाग कर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। तकनीकी आधार पर तलाश शुरू करने पर मामले में तीन बदमाशों को दबोच लिया गया। अलग-अलग स्थानों से पकड़ में आए इन आरोपियों में रूढ़ी (खिवांडा-पाली) हाल सूरत निवासी सवाईसिंह उर्फ सोनू पुत्र सुरेंद्रसिंह रावपुरोहित, दातराई रेवदर निवासी शिशुपालसिंह पुत्र हरिसिंह राव व कालन्दी निवासी राजेंद्रसिंह पुत्र मंगलसिंह शामिल हैं। मामले में अन्य बदमाशों को भी नामजद किया गया है, जिनकी सरगमों से तलाश की जा रही है।

छिपते हुए काट रहा था फरारी

पुलिस के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी सवाईसिंह उर्फ सोनू पर राजस्थान व गुजरात में कई मामले दर्ज हैं। सूरत में हित एंड रन, चाकूबाजी, वस्ती, सुमेरपुर में फिरोती, फायर, हत्या में संलिप्तता, बाली में मारपीट, हमला करने जैसे कई मामले दर्ज हैं। वह जोधपुर, सूरत व जैसलमेर समेत अलग-अलग जगहों पर छिपते हुए फरारी काट रहा था।

पंचायतीराज चुनाव-2026 : मतदान से लेकर मतगणना तक हर तैयारी की हुई समीक्षा

- जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरुण कुमार हसीजा ने ली सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों व एसडीएम की पहली बैठक
- निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हों, हर नियम की अक्षरशः पालना करें : हसीजा

बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (सुरेश बागोरा)। आगामी पंचायतीराज चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) अरुण कुमार हसीजा ने मंगलवार सायं जिला परिषद सभागार में सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी अधिकारियों एवं सभी एसडीएम की पहली समन्वय बैठक आयोजित की। बैठक में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (एडीएम) नरेश बुनकर, जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, मंदिर मण्डल नाथद्वारा सीईओ जितेंद्र पांडे, एडिशनल एसपी रजत विशनोई सहित सभी प्रकोष्ठ प्रभारी, जिले के सभी उपखंड अधिकारी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन



अधिकारी हसीजा ने निर्देश दिए कि निर्वाचन की अधिसूचना जारी करने से लेकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्ति, संवीक्षा, नाम वापसी, चुनाव चिह्न आवंटन, अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने, पहचान पत्र जारी करने तथा राज्य निर्वाचन आयोग को समस्त सूचनाएं समय पर प्रेषित करने की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्रमुख एवं उप प्रमुख के चुनाव सहित आरओ सेल से संबंधित समस्त कार्य समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निर्वाचन प्रक्रिया में समन्वय, मॉनिटरिंग और पारदर्शिता पर जोर

हसीजा द्वारा जिला निर्वाचन अनुभाग को आयोग से प्राप्त पत्रों का त्वरित संप्रेषण, निर्वाचन नामावली की तैयारी, मतदान केंद्रों का प्रकाशन तथा वीडियो



कॉन्फ्रेंस बैठकों को एंजेंडवार तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कानून व्यवस्था प्रकोष्ठ को एरिया एवं जोनल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, धारा 163 बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत निषेधाज्ञा, कोलाहल नियंत्रण, संपत्ति विवरण अधिनियम, पोस्टर-बैनर नियंत्रण, सूखा दिवस घोषणा तथा अनुसूच शस्त्र जमा कराने जैसी कार्यवाहियां समय पर पूर्ण करने को कहा गया। संस्थापन प्रकोष्ठ को चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा एमसीसी अवधि में कार्यग्रहण व कार्यमुक्ति संबंधी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। सामान्य व्यवस्था प्रकोष्ठ को मतदान दल रवानगी एवं संग्रहण स्थलों पर मूलभूत सुविधाएं, स्टून्ग रूम चयन एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

मतदान, मतगणना, प्रशिक्षण व सुरक्षा व्यवस्थाओं की रूपरेखा तय

मतदान एवं मतगणना दल गत प्रकोष्ठ को कार्मिकों का डाटा संघान, रेंडमइजेशन, आवास, पेयजल, बिजली, परिवहन एवं कंट्रोल रूम स्थापना की तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ को प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चरणबद्ध प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस बल को क्रिटिकल एवं वलन्टेबल मतदान केंद्रों की पहचान, सुरक्षा प्लान तैयार करने, सशस्त्र बल तैनाती तथा नियमित एलओआर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। मतपत्र मुद्रण, ईवीएम कमीशनिंग, रेंडमइजेशन, परिहान एवं स्टून्ग रूम सुरक्षा के लिए संबंधित प्रकोष्ठों को समन्वित कार्यवाही के निर्देश दिए गए।

प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव करवाने की मांग एडवोकेट देवांश सिंह ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन

बढ़ता राजस्थान

पावटा (नि.स.)। कांग्रेस नेता एवं जयपुर हाईकोर्ट के अधिवक्ता देवांश सिंह ने प्रदेशभर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव पुनः प्रारंभ करवाने की मांग को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। देवांश सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा उच्च शिक्षा मंत्री व उपमुख्यमंत्री प्रेमचन्द बैरवा को भेजे ज्ञापन में छात्रहितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र चुनाव कराने की मांग उठाई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में छात्रसंघ चुनावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परिस्थितियों के चलते छात्रसंघ चुनाव स्थगित कर दिए थे। अब जबकि शैक्षणिक वातावरण सामान्य हो चुका है, ऐसे में इस वर्ष प्रदेशभर में पूर्व की भांति नियमित और सुचारु रूप से छात्रसंघ चुनाव करवाना आवश्यक है। देवांश सिंह ने कहा कि प्रदेश के हजारों विद्यार्थी छात्रसंघ चुनावों की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं समयबद्ध कार्यक्रम घोषित कर चुनाव संपन्न कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होते हैं। इन्होंने चुनावों से छात्र नेतृत्व उभरता है, जो आगे चलकर प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाता है।

छात्रसंघ व्यवस्था युवाओं में नेतृत्व क्षमता, संगठन कौशल और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करती है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूती प्रदान करती है। देवांश सिंह द्वारा ज्ञापन के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में शीघ्र आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर छात्रसंघ चुनाव आयोजित कराए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का उनका अधिकार सुनिश्चित हो सके।

जिला स्तरीय कृषि एवं उद्यानिकी समितियों की बैठक सम्पन्न

विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लक्ष्य अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश

बढ़ता राजस्थान

राजसमंद (सुरेश बागोरा)। जिला कलक्टर अरुण कुमार हसीजा की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय कृषि समिति, जिला उद्यानिकी विकास समिति, आत्मा शासी परिषद, जिला स्तरीय निगरानी समिति (फसल बीमा), जिला स्तरीय उर्वरक नियंत्रण समिति, जिला स्तरीय तिलहन मिशन तथा जिला स्तरीय क्रियाव्यवस्था समिति (तिलहन) की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की शुरुआत संयुक्त निदेशक कृषि भूपेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा स्वागत उद्बोधन से की गई। उन्होंने पीपीटी के माध्यम से कृषि, उद्यानिकी एवं आत्मा अंतर्गत गठित विभिन्न समितियों एवं उनके कार्यों की जानकारी प्रस्तुत की। डीबीटी योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि सिंचाई पाइपलाइन, कृषि यंत्र, फार्म पौड, तारबंदी, गोवर्धन जैविक उर्वरक एवं कृषि संकायों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जैसी योजनाओं में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई हैं। जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि अधिक से अधिक कृषकों के आवेदन प्राप्त कर लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृतियां जारी की जाएं।

आपसे प्रेम सहयोग सम्मान ही सच्चा जीवन है-बबीता दीदी

डीग में श्री ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई प्रमात फेरी व किया शिव ध्वजारोहण

बढ़ता राजस्थान

डीग (नि.स.)। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उप सेवा केंद्र डीग की ओर से मंगलवार को महाशिवरात्रि का पावन पर्व ब्रह्माकुमारी बबीता दीदी की अध्यक्षता में ब्रह्मा और उत्साह के साथ मनाया गया। भीविशिष्ट अतिथि हिंदी साहित्य समिति डीग के महामंत्री भगवान शरण, राजयोग शिक्षिका एवं प्रभारी डीग ब्र. कु. प्रवीणा बहिन, योगिता बहिन एवं जागृति बहिन थीं।

कार्यक्रम की शुरुआत ईश्वरीय स्मृति गीत ऐ आत्माओंं सुन लो शिव ये शुभ संदेश से हुई। मुख्य अतिथि संत दास बाबा ने कहा कि परमात्मा शिव एकांतवासी हैं और उनकी प्राप्ति के लिए मीन व एकांत आवश्यक है। समय स्वयं के समान है, इसे व्यर्थ न

गवाएं। उन्होंने ईर्ष्या, निंदा और चुगली से दूर रहने का संदेश देते हुए सभी को महापर्व की शुभकामनाएं दीं।

अध्यक्षीय उद्बोधन में बबिता दीदी ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कहा कि यह परमात्मा के अवतरण का दिवस है। नमक और मिर्च त्यागने का अर्थ कड़वे और तीखे वचनों का त्याग करना है। आपसी प्रेम, सहयोग और सम्मान ही सच्चा जीवन है।

चंद्रभान वर्मा ने घर-घर शिव का ध्वज फहराएंगे कविता प्रस्तुत की। ब्रह्माकुमारी योगिता बहिन ने परमात्मा को निराकार ज्योति विंदु स्वरूप बताया।

कार्यक्रम से पूर्व कस्बे में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सजाई गई शिव शंकर एवं राधा-कृष्ण की झांकियां सभी के आकर्षण का केंद्र रही। प्रभात फेरी को संत



दास बाबा राजा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अतिथियों ने शिव ध्वजारोहण कर

मन, वचन, कर्म से किसी को दुख न देने की प्रतिज्ञा दिलाई।

जेईई मेन परीक्षा में डीपीएस के 10 विद्यार्थियों का श्रेष्ठ प्रदर्शन

बढ़ता राजस्थान

उदयपुर (नि.स.)। दिल्ली पब्लिक स्कूल, उदयपुर के नौ विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जॉइंट एंटेस एक्जाम-जेईई मेन-2026 परीक्षा में 90 पर्सेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। विद्यालय के प्राचार्य संजय नरवरिया ने बताया कि अध्ययन के प्रति समर्पित देव गहलोट (99.88), वैभव कच्छारा (99.53), दक्षिणा अग्रवाल (99.13), काव्या चिराग कोठारी (98.6), श्रेष्ठ शर्मा (97.59), धनंजय अग्रवाल (95.69) अहोना सेन (95.27), वंशिका कुमावत (94.5), निरंजं जैन (92.33), शिनि बाबेल (91.74) ने अपने अथक परिश्रम व लगन से यह सफलता अर्जित की है।

Dev Gehler 99.88 %ile	Vaibhav Kachhara 99.53 %ile	Dakshita Agarwal 99.13 %ile	Kavya Chirag Kothari 98.6 %ile	Shresth Sharma 97.59 %ile
Dhananjay Agrawal 95.69 %ile	Ahona Sen 95.27 %ile	Vanisha Kumawat 94.5 %ile	Nirhan Jain 92.33 %ile	Shini Babel 91.74 %ile

की है। विद्यालय के प्रो वाइस चेरमैन श्री गोविंद अग्रवाल ने बताया कि ये सभी छात्र प्रारंभ से ही होनहार और परिश्रमी हैं। इन्होंने अब तक की सभी

परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा के बल पर सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त किए हैं। ये सभी छात्र अप्रैल माह में होने वाली जेईई मेन परीक्षा में भाग लेंगे। छात्रों की इस सफलता पर प्राचार्य संजय नरवरिया व उप प्राचार्य राजेश धर्माई ने छात्रों व उनके अभिभावकों को बधाई दी और जेईई की अप्रैल की परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दीं।

कैटल शेड के लिए 80 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

- दस कैटल शेड पास करने की एवज में जेटीए ने ली रिश्वत - रेवदर पंचायत समिति की उड़वारिया पंचायत का मामला

बढ़ता राजस्थान

सिरोही (नि.स.)। रेवदर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत उड़वारिया में कैटल शेड बनाने की एवज में 80 हजार रुपए रिश्वत ले रहे जेटीए को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। उसने दस शेड पास करने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जयपुर से आई विशेष टीम ने ट्रेप कार्रवाई को अंजाम दिया।

जानकारी के अनुसार रेवदर में कार्यरत जूनियर टेक्निकल एफिसर जेटीए दिनेश वैष्णव को रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया है। उसने ग्राम पंचायत उड़वारिया में दस कैटल शेड बनाने की एवज में प्रति शेड दस-दस हजार रुपए की रिश्वत मांगी। राशि जमाद होने से मामला बातचीत से तय किया गया। इसके बाद जेटीए ने प्रति कैटल शेड आठ-आठ हजार रुपए मांगे। दस



कैटल शेड पास करने की एवज में 80 हजार रुपए में मामला तय किया गया। परिवादी ने जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को इसकी शिकायत प्रस्तुत की।

सत्यापन के बाद विशेष टीम ने ट्रेप कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी टीम ने रेवदर में पंचायत समिति के बाहर जेटीए को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

उदयपुर में बीसीआई के तीनों चैटर्स की संयुक्त आधिकारिक बैठक आज, तीनों चैटर्स के जुटेंगे सदस्य, बिजनेस नेटवर्किंग पर होगा मंथन

बढ़ता राजस्थान

उदयपुर (नि.स.)। बिजनेस सर्कल इंटरनेशनल (बीसीआई) के बीसीआई अल्फा, बीसीआई उत्सव और बीसीआई युवा की संयुक्त आधिकारिक बैठक बुधवार 18 फरवरी को होगी।

बीसीआई के फाउंडर एंड चेरमैन मुकेश माधवानी ने बताया कि होटल जगत में शाम 6 बजे से शुरू होने वाली इस आधिकारिक बैठक में बीसीआई अल्फा, बीसीआई उत्सव और बीसीआई युवा के सदस्य एक ही छत के नीचे जुटेंगे। उन्होंने बताया कि इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु बिजनेस इकोसिस्टम को मजबूत करना है, जिसके तहत आगामी बिजनेस कॉम, वूमंस डे सेंसिब्रेशन और बीसीआई एनुअल रिवाइस जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। साथ ही, तकनीक के माध्यम से व्यापार को सुगम बनाने के लिए एक विशेष बिजनेस मैनेजमेंट एप और गिव एंड गेटिंग प्लान पर चर्चा होगी, जो सदस्यों के बीच आपसी लेन-देन और व्यावसायिक पारदर्शिता को नए आयाम प्रदान करेगा। बीसीआई अल्फा के अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह करीर ने कहा कि यह आयोजन केवल एक बैठक मात्र नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के बीच समन्वय स्थापित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें व्यापारिक चुनौतियों के समाधान, बाजार की वर्तमान स्थिति और संगठन को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढालने के लिए रणनीतिक चर्चा की जाएगी, ताकि हर उद्यमी को प्रगति के समान अवसर मिल सकें। उन्होंने बताया कि बैठक में बिजनेस प्रेजेंटेशन होगा। साथ ही, पिछले सत्र में हुए बिजनेस एक्सचेंज के आंकड़े भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा बेस्ट परफॉर्मिंग पर सदस्यों को रिवॉर्ड भी मिलेगा। बीसीआई उत्सव के अध्यक्ष संजीव पटवा ने बताया कि बैठक के दौरान सामूहिक व्यापारिक गतिविधियों और श्रेफरल बिजनेस मॉडल पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

**चौधरी और यादव डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित!
स्काउटिंग के क्षेत्र में विशेष
योगदान सहित अनेक गतिविधियों
के लिए मिला सम्मान**



बढ़ता राजस्थान

बानसूर (धीरज मोर्वे)। विधानसभा क्षेत्र से राजस्थान भारत स्काउट/गाइड के स्थानीय संघ के सहायक लीडर ट्रेनर राजेन्द्र सिंह चौधरी व कृष्ण कुमार यादव को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह उपाधि हिमालय बुड बैचधारी को ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी चेन्नई स्थित भारतीय विद्या भवन के ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में दी गई। उक्त दोनों को यानी राजेन्द्र सिंह चौधरी व कृष्ण कुमार यादव को स्काउटिंग के क्षेत्र में विशेष योगदान, युवा सशक्तिकरण नेतृत्व विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। डॉ चौधरी और डॉ यादव ने बताया कि हम इसका श्रेय नेशनल कमिश्नर एडल्ट रिमोस नई दिल्ली के डॉ. सुकुमार के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में मिला है। हम दोनों डॉ सुकुमार का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बानसूर आगमन पर स्थानीय राजस्थान भारत स्काउट एवं गाइड संघ के पदाधिकारियों द्वारा डॉ चौधरी व डॉ यादव का माला साफा पहनाकर भव्य सम्मान किया गया और उनका मुँह मीठा कराकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। यह जानकारी हमें एसएमएस निजी विद्यालय के शारीरिक शिक्षक राजकुमार शर्मा द्वारा भेजे गए प्रेस नोट से प्राप्त हुई। राजकुमार शर्मा ने अलवर के सीओ स्काउट राजेन्द्र मीणा व गाइड सीओ विजय लक्ष्मी द्वारा भेजे गए प्रेस नोट द्वारा प्राप्त हुई।

**वन मंत्री संजय शर्मा का जन्मदिन
धूमधाम से मनाया गया**



बढ़ता राजस्थान

अलवर। अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा अलवर की ओर से मनाया गया वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से

मंगलवार को राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री माननीय संजय शर्मा का 57 वा जन्मदिवस अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा अलवर के बैनर तले हरियाणा ब्राह्मण समाज की ओर से बड़ी धूमधाम से मनाया गया, इस अवसर पर प्रातः 8:00 बजे बुध विहार स्थित नंदी गोशाला में समाज बंधुओं द्वारा गोवंशों को हरा चारा खिलाया गया एवं इसके बाद सायं 6:30 बजे श्री त्रिपोलिया महादेव मंदिर में भगवान महादेव की महाअरती का आयोजन किया गया महाअरती पश्चात ही 121 किलो केसर युक्त दूध का भोग लगाकर आमजन में प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय के पुत्र निक्कुंज शर्मा अध्यक्ष मनोज शर्मा मंत्री जय किशन शर्मा उप मंत्री नरेश कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष रामअवतार शर्मा उमाशंकर शर्मा जितेन्द्र शर्मा पुरुषोत्तम शर्मा कैलाश चंद शर्मा राजेश शर्मा नरेंद्र शर्मा नरेश शर्मा गंगा सहाय शर्मा गिरांज प्रसाद गावड़ी कैलाश शर्मा महेश शर्मा बलराम शर्मा सुरेश शर्मा राजू शर्मा सुनील शर्मा अंजु शर्मा संतोष शर्मा विशाल शर्मा राजेंद्र शर्मा सुरेंद्र शर्मा सुनील ओजट राकेश शर्मा विद्याधर शर्मा ललित शर्मा महेश बबलू हरिओम शर्मा आदि अनेक समाज बंधु सहित भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेन्द्र राठौर महेश निहालवाणी रवि यादव दिनेश गुप्ता घनश्याम गुप्ता उपस्थित रहे, इस अवसर पर उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने माननीय संजय शर्मा के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन के लिए भगवान महादेव से मनोकामना मांगी।

**अंकतालिका डाउनलोड करने के लिए
राज ई-वॉल्ट का उपयोग करें विद्यार्थी**

बढ़ता राजस्थान

अजमेर (मोहित जैन)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों को अंकतालिका डाउनलोड करने के लिए राज ई-वॉल्ट का उपयोग करने की सलाह दी है। बोर्ड सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि विद्यार्थी पुराने तरीके से मार्कशीट डाउन लोड कर रहे हैं जबकि डीजी लॉकर में उपलब्ध राज ई-वॉल्ट (Raj eVault) सर्विस के अंतर्गत विद्यार्थियों का डेटा अपडेटेड उपलब्ध है। डी.जी. लॉकर पर डेटा अद्यतन की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह व्यवस्था की गई है। अतः विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि कक्षा 10 वीं एवं कक्षा 12 वीं की परीक्षा वर्ष 2015 से वर्ष 2025 तक के प्रमाण पत्र डी.जी लॉकर में उपलब्ध राज ई-वॉल्ट सर्विस से प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया डी.जी. लॉकर पर लॉगईन कर सर्व डॉक्यूमेंट में राज ई-वॉल्ट सर्व कर, उपलब्ध राज ई-वॉल्ट ऑप्शन में कक्षा, नाम, रोल नम्बर, परीक्षा वर्ष भरें और गेट-डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं।

**खनिज का अवैध खनन एवं निर्गमन करने पर की कार्रवाई
नवम्बर 2025 से अब तक 11 प्रकरणों में
करीब 12 लाख रुपये की वसूली गई राशि**

बढ़ता राजस्थान

राजगढ़ (अलवर)। खनिज अभियन्ता मनेज शर्मा ने बताया कि खान एवं पुलिस विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा आज अवैध खनन एवं निर्गमन की रोकथाम हेतु ग्राम जटियाना, भटेसरा, सताना, बिलन्दी, गुरू गोडडी, राजगढ़ इत्यादि स्थानों पर अवैध खनन के संवेदनशील क्षेत्रों में आकस्मिक जांच की गई। इस दौरान खनिज बजरी का एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर पुलिस थाना राजगढ़ तथा खनिज मैनेजरी स्टोन के अवैध खनन में लिप्त एक ट्रैक्टर ट्रॉली जहूर खान निवासी जटियाना से जब्त कर पुलिस थाना विजय मंदिर को सुर्गद किया।

**बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति के लिए भूमि
आवंटन की प्रक्रिया को देवें गति- जिला कलक्टर**

**जिला कलक्टर ने ली बजट घोषणाओं 2026-
27 के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक**



बढ़ता राजस्थान

अलवर। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिक शुकला ने आज कलक्टर सभागार में बजट घोषणाओं 2026-27 के समयबद्ध क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। जिला कलक्टर ने बजट 2026-27 में जिले के लिए हुई घोषणाओं की विभागवार समीक्षा कर निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति के लिए विभागीय अधिकारी भूमि की आवश्यकता वाली घोषणाओं के लिए सात दिवस में भूमि आवंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें, जिससे आमजन की सुविधाओं के दृष्टिगत बजट घोषणाओं को यथाशीघ्र धरातल

पर मूर्त रूप दिया जा सके। उन्होंने उद्यान विभाग के उपनिदेशक को निर्देश दिये कि ब्याज एवं सब्जी के लिए सेंटर आफ एक्सप्लोस की स्थापना हेतु गाइडलाइन अनुसार आवश्यक भूमि के लिए भूमि आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। उन्होंने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि राजगढ़ शहर में पेयजल व्यवस्था सुदृढीकरण कार्य के संबंध में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारम्भ करावें। जिला कलक्टर ने सरस डेयरी के महाप्रबंधक को निर्देशित किया कि 200 करोड़ रुपए की लागत के x लाख लीटर प्रति दिन क्षमता के दूध प्लांट के लिए आवश्यक प्रक्रिया को यथासमय पूर्ण

करावें। उन्होंने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि अलवर शहर के अम्बेडकर नगर, कठूमर के खोह एवं रामगढ़ के नंगली मेधा में xx/11 केवी के जीएसएस के लिए भूमि के आवंटन के संबंध में आवंटन प्रक्रिया पूर्ण करें। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियन्ता को निर्देश दिये कि कुशालगढ़ तिराहे से थैक्यू बोर्ड वाया भर्तुहरि सडक तक व नौगांवा से नसवारी चौकी तक की सडक निर्माण हेतु सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर कार्य गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप में कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि अलवर जिले के लिए की गई बजट घोषणाओं के साथ-साथ ऐसी बजट घोषणाएं

जो सम्पूर्ण राय के लिए हैं, उन घोषणाओं को भी मूर्त रूप देने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर शहर बीना महावर, अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय योगेश डागु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता रमेश चंद सैनी, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियन्ताभुरी सिंह, जयपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियन्ता आर.डी बंसल, सीएमएचओ डॉ. योगेन्द्र शर्मा, कृषि विभाग के संयुक्तनिदेशक पी.सी मीणा, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक रमेश चंद मीणा, उद्यान विभाग के उप निदेशक के.एल मीणा, सीडीईओ महेश गुप्ता सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

**डीलर्स एसोशियेशन की बैठक में हुआ
चुनाव, हुआ नवीन कार्यकारिणी का गठन**

बढ़ता राजस्थान

बानसूर (धीरज मोर्वे)। विधानसभा क्षेत्र की बानसूर नगर पालिका क्षेत्र के डीलर्स एसोसिएशन के व्यापारियों की एक अहम बैठक हुई। बैठक में डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद सहित अन्य व्यापारिक मण्डलों के चुनाव पर गहन मंत्रणा हुई। जिसमें डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर मुकेशसिंह शेखावत को सर्वसम्मति से निर्वाचन चुना गया। तो वस्त्र व्यापार यूनियन में दिनेश सिंघल को निर्वाचन निर्वाचित किया गया। वहीं डीलर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त मुकेश सिंह शेखावत ने कहा कि व्यापार मण्डल में नियुक्त सभी सदस्य सम्माननीय हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह नहीं जो समझा



जाता है। वह नजर नहीं आता! वहीं व्यापार मण्डल अध्यक्ष के माननीय मुकेशसिंह शेखावत ने कहा कि उपाध्यक्ष पद पर अनील सिंघल, कोषाध्यक्ष पद पर लक्ष्मण गुप्ता, संगठन मंत्री सुदेश अग्रवाल सचिव अविनाश गोयल, को मनोनीत किया गया गया है। वहीं वस्त्र व्यापार मण्डल यूनियन के वस्त्र व्यापारी,

कार्यकारिणी के सर्वसहमति से चुनाव वस्त्र व्यापार मण्डल के अध्यक्ष पद पर सिंघल को चुना गया है। वहीं व्यापार मण्डल के विभन संगठनों में हुए चुनावों में व्यापार मण्डल के अध्यक्ष एवं संगठन द्वारा की गई कार्यकारिणी का विस्तार इस प्रकार है। अध्यक्ष पद पर दिनेश सिंघल, उपाध्यक्ष

पद पर महेश छीलवाल, कोषाध्यक्ष पद पर सुनील अग्रवाल, सचिव पद पर सतीश अग्रवाल, प्रचार मंत्री पद पर दिनेश अग्रवाल को निर्वाचन निर्वाचित किया गया है। वहीं लक्ष्मण गुप्ता, सुदेश अग्रवाल, अविनाश गोयल, दिनेश अग्रवाल सहित काफी संख्या में व्यापार मण्डल के सदस्य मौजूद रहे।

**अनीमिया की दर को
कम करने हेतु आयोजित
हुआ शक्ति दिवस**



बढ़ता राजस्थान

टोंक (पुरुषोत्तम जोशी)। अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के प्रभाव को क्रियान्वयन हेतु शक्ति दिवस आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शैलेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि अनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों, किशोर-किशोरियों, प्रजनन उम्र की महिलाओं, गर्भवती महिलाओं तथा धात्री माताओं में अनीमिया की दर को कम करने हेतु जिले में माह के प्रत्येक मंगलवार को 'शक्ति दिवस' के रूप में मनाया जाता है। डॉ. चौधरी ने बताया कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों, पीएचसी, सीएचसी व राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर शक्ति दिवस आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय व लाभार्थियों में अनीमिया नियंत्रण हेतु स्क्रीनिंग, हिमोग्लोबीन की जांच उपचार तथा अनीमिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। डॉ. चौधरी ने बताया कि उक्त दिवस पर अनीमिया से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गईं। जिसमें अनीमिया की स्क्रीनिंग, जांच, उपचार तथा अनीमिया के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये।

**गर्भवती महिलाओं को परामर्श के साथ पांच वर्ष तक के बच्चों को लगाए टीके
अर्बन पीएचसी ने लगाया शहर के
चेतन नगर काली माता क्षेत्र में शिविर**

बढ़ता राजस्थान

बाड़ी। शहर की कच्ची वस्तियों और आउटरीच एरिया में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अब स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (अर्बन पीएचसी) द्वारा शहर के चेतन नगर में काली माई मंदिर के पास आज शिविर का आयोजन किया गया।



इस शिविर में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, 0 से 05 वर्ष आयु के छोटे बच्चों का टीकाकरण करने के साथ मौसमी बीमारियों के रोगियों को परामर्श दिया गया वहीं बीपी, शुगर, प्रेशर की जांच की गई साथ में एमसीडी जांच भी हुई। शिविर के दौरान करीब 5 दर्जन लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर का आयोजन पीएचसी प्रभारी डॉ घनश्याम कुशवाहा के नेतृत्व में किया गया। डॉ घनश्याम कुशवाहा ने बताया कि अर्बन पीएचसी द्वारा शहर के उन स्थानों पर यह शिविर आयोजित किये जा रहे हैं जो शहर

के सामान्य अस्पताल या अर्बन पीएचसी से काफी दूरी पर है और वहां के रोगी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे में शिविर का आयोजन आज चेतन नगर कालीबाई मंदिर पर किया गया है। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच हुई है और

**अनावड़ा में कल होगा आदिवासी मीणा समाज
के 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन**



बढ़ता राजस्थान

राजगढ़ (अलवर)। उपखंड क्षेत्र के गांव अनावड़ा में 19 फरवरी 2026 को फुलरा दूज के शुभ अवसर पर आदिवासी मीणा समाज के 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन आदिवासी मीणा समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के तत्वावधान में संत बाबा रामदेव आश्रम के पास तैयार किए गए विशाल सम्मेलन स्थल पर संपन्न होगा।

सम्मेलन समिति के संयोजक इंजीनियर रामगोपाल मीणा ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। राजगढ़ परिक्षेत्र में आयोजित हो रहे मीणा समाज के इस प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर स्थानीय ग्रामवासियों और आसपास के गांवों में उत्साह का माहौल है। समिति के कार्यकर्ता दिन-रात मेहनत कर कार्यक्रम को भव्य और सफल बनाने में जुटे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि सम्मेलन में वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। समिति पदाधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के सामूहिक विवाह आयोजनों से समाज में व्याप्त कुटीरियों और फिजूलखर्ची पर रोक लगेगी तथा सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन को लेकर पूरे क्षेत्र में व्यापक तैयारियां और उत्साह देखा जा रहा है।

**हाईकोर्ट चीफ जस्टिस का
औचक निरीक्षण, नदारद
मिले 8 जज एपीओ**

बढ़ता राजस्थान

जोधपुर। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नदारद मिले 8 जजों पर प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए इन्हें एपीओ कर दिया गया है।

न्यायिक अधिकारियों को एपीओ कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा की ओर से आदेश जारी कर 8 न्यायिक अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से 'पदस्थान आदेशों की प्रतीक्षा' में रख दिया गया। इनमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जोधपुर महानगर अजय शर्मा, विशेष न्यायालय (अपर पाँवसो एक्ट के संख्या 1 (जोधपुर महानगर) की जज मनीषा चौधरी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2, जोधपुर महानगर मनीषा शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर जिला नेहा शर्मा, सीनियर सिविल जज एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला करुणा शर्मा, अपर सीनियर सिविल जज एवं एसीजेएम संख्या 2, जोधपुर महानगर प्रवीण चौधरी, अपर सीनियर सिविल जज एवं एसीजेएम संख्या 9, जोधपुर महानगर सीमा सांडू और अपर सीनियर सिविल जज एवं एसीजेएम संख्या 7, जोधपुर महानगर मनेज जीनार के नाम शामिल हैं। एपीओ किए गए इन अधिकारियों में से अजय शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में अपनी उपस्थिति देने को कहा गया है। वहीं अन्य सात जजों को जिला व सत्र न्यायालय मुख्यालय पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है।

दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट की बम से उड़ने की धमकी मिली जिस कारण से सुरक्षा एजेंसियां तलाशी में जुटी रही। हाईकोर्ट प्रशासन को मंगलवार सुबह एक ईमेल मिला था, जिसमें परिसर में बम होने की धमकी दी गई थी। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली कराया गया जिसके कारण सुबह कामकाज प्रभावित रहा और डिस्टले बोर्ड पर भी सूचना जारी की गई थी। इस बीच कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा हाईकोर्ट हेरिटेज बिल्डिंग परिसर की कार्यवाही बीच पहुंच गए। उन्होंने वहां स्थित विभिन्न जिला, महानगर और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों का औचक निरीक्षण किया।

इस दौरान कई कोर्ट रूम खाली पाए गए और कई न्यायिक अधिकारी नदारद मिले। अनुशासन और समयबद्धता को लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इस लापरवाही को गंभीरता से लिया और 8

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र चंगवरिया पाड़ा में कैप का आयोजन किया गया। जिसमें छोटे बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान केंद्र से जुड़ी महिलाओं के छोटे बच्चों को टीके लगाए गए।

हिमंता बोले-2014 में सोनिया मुझे सीएम बनाने को तैयार थीं राहुल ने नेताओं को फोन कर हालात बदल दिए, लेकिन जो होता है अच्छा होता है



गुवाहाटी।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को दावा किया कि 2014 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मुझे मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की थी। कहा था कि मैं शपथ लेने की तारीख तय करूँ। उस वक्त कांग्रेस के 58 विधायक मेरे समर्थन में थे। सरमा ने पत्रकारों को बताया, 'मैंने उनसे (सोनिया) कहा था कि वे जून 2014 में कामाख्या मंदिर में होने वाले अंबुबाची मेले के अगले दिन शपथ लेंगे। लेकिन उस समय अमेरिका में मौजूद राहुल ने पार्टी नेताओं को फोन किए और हालात बदल गए।'

सरमा ने 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और 2015 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। 2021 में असम के मुख्यमंत्री बने।

मुख्यमंत्री ने कहा- तब सीएम बन जाता तो शायद छवि खराब हो जाती

भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे असम और सनातन धर्म की सेवा करने का अवसर मिला, जो कांग्रेस में रहकर संभव नहीं था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इसके लिए वे राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे असम आए थे, तब 58 कांग्रेस विधायक उनके समर्थन में थे। कुछ नेता तटस्थ थे और केवल 12 विधायक चाहते थे कि तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ही बने रहें। मुझे न्याय नहीं मिला, लेकिन खड़गे उनके विरोधियों से कहते थे कि हिमंत से लड़िए, लेकिन विधायक मेरे साथ थे। अगर मैं उस समय मुख्यमंत्री बन जाता तो शायद मेरी छवि खराब हो जाती। इन बातों के कई गवाह हैं और वे भविष्य में अगर किताब लिखेंगे तो विस्तार से बताएंगे। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के पाकिस्तान से संबंध हैं। जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं और भी नेता इस मुद्दे पर बोलेंगे। 2012 में ही तय कर लिया था कि वे बाहर से थोपे गए नेताओं के सामने नहीं झुकेंगे। उस समय मंत्रियों को गौरव गोगोई की बैठकों में जाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। कांग्रेस का माहौल ऐसा है कि साधारण परिवारों के लोग वहां टिक नहीं पाते। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा से आज (मंगलवार) को मुलाकात की है। बोरा 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे।

असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाजपा जाँइन करेंगे

22 फरवरी को सदस्यता, सीएम हिमंत ने मुलाकात की

बढ़ता राजस्थान

गुवाहाटी। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा के भाजपा जाँइन करने की अटकलों पर आखिरकार मुहर लग गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार शाम बोरा के घर जाकर उनसे मुलाकात की। इसके बाद सीएम ने बोरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि वे 22 फरवरी को पार्टी की सदस्यता लेंगे। बोरा ने एक दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उन्होंने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा। बोरा ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि उन्हें पार्टी नेतृत्व की ओर से नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि, उनके इस्तीफे को लेकर आज पूरे दिन असमजस की स्थिति रही। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी ईंचार्ज जितेंद्र सिंह ने कल कहा था कि बोरा ने इस्तीफा वापस ले लिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा था कि राहुल गांधी ने बोरा से 15 मिनट बात की है। भूपेन बोरा ने कहा था कि वे इस्तीफे पर मंगलवार को अंतिम निर्णय लेंगे। बोरा ने कहा- 32 साल बाद मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। अब समय लेकर सोचने की आवश्यकता है। कई वरिष्ठ नेताओं और साथी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुझे सभी पहलुओं पर विचार करने को कहा है।

हिमंत बोले- बोरा की तरह मैंने भी दर्द सहा

हिमंत ने बोरा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा में शामिल होने से बोरा सच्ची छवि बनेंगे। भूपेन बोरा के साथ गुवाहाटी और उत्तरी लखीमपुर में कांग्रेस के कई नेता 22 फरवरी को भाजपा में शामिल होंगे। हिमंत ने कहा- कांग्रेस अब असमिया लोगों को पार्टी नहीं रही। पार्टी चुनाव जीतने के लिए संघर्ष नहीं कर रही है। कोई भी सच्चा कांग्रेसी इस बात से दुखी होगा। मैंने भी यही दर्द सहा है। जब मैं भाजपा में शामिल होने गया था, तब मुझे भी ऐसे फोन आते थे। ये लोग सामंती की तरह जीते हैं। उन्हें लगता है कि एक फोन करने से फैसला बदल जाएगा।

विराट-अनुष्का वृंदावन पहुंचे, प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया

भक्तों के साथ हाथ-जोड़कर बैठे रहे; एक घंटे तक सलंग सुना



बढ़ता राजस्थान

मथुरा (एजेंसी)। क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ मंगलवार सुबह 6 बजे प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे। एक घंटे तक प्रेमानंद महाराज का सत्संग सुना। इस दौरान दोनों हाथ जोड़कर बैठे रहे। सत्संग सुनने के बाद प्रेमानंद महाराज से आशीर्वाद लिया। हालांकि, इस दौरान बेटी वाभिका साथ नहीं थी।

विराट-अनुष्का सोमवार शाम को दिल्ली से वृंदावन पहुंचे थे। यहां एक होटल में रहे। फिर मंगलवार सुबह प्रेमानंद जी के केली कुंज आश्रम पहुंचे। आश्रम से जुड़े लोगों के अनुसार, वे तय समय से पहले ही पहुंच गए थे और भक्तों के साथ सत्संग में शामिल हुए। दर्शन और सत्संग के बाद दोनों दिल्ली लौट गए।

वापसी के दौरान आश्रम के बाहर उनकी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई। विराट के मौजूद होने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में प्रशंसक पहुंच गए। मौके पर मौजूद पुलिसवालों ने भीड़ को कंट्रोल कर लगभग 15 मिनट में रास्ता साफ कराया, तब जाकर उनकी गाड़ी आगे बढ़ सकी।

बीकानेर-नागौर में ओले गिरे, 6 जिलों में बारिश

जयपुर।

राजस्थान के नागौर और बीकानेर में मंगलवार को बारिश के साथ ओले गिरे। सीकर, पाली, श्रीगंगानगर और डीडवाना-कुचामन में भी बरसात हुई। बीकानेर, जयपुर, अजमेर के साथ जोधपुर संभाग के जिलों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 18 फरवरी को रहेगा। जयपुर सहित कई जिलों में मंगलवार सुबह से तेज हवा चली और बादल छाए थे।

दिन का तापमान 35 डिग्री के करीब

इससे पहले पिछले 24 घंटे में राज्य में सभी जगह आसमान साफ रहा। दिन में

तेज धूप रही। सिरोंही, हनुमानगढ़ और बारां को छोड़कर सोमवार को शेष सभी शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज हुआ।

25 जिलों के लिए अलर्ट

मौसम विशेषज्ञों ने बताया- राज्य में आज से आया मौसम परिवर्तन का दौर 18 फरवरी को भी जारी रहेगा। बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। बादल छाने के साथ-साथ कहीं-कहीं तेज हवा चल सकती है और ओले भी गिर सकते हैं। बुधवार को 25 जिलों में बदले मौसम का असर दिखेगा।



तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने

मंत्रिमंडल में 1 हिंदू-1 बौद्ध समेत 49 मंत्री; पीएम मोदी ने भारत आने का न्योता दिया

बढ़ता राजस्थान

ढाका। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक को पीएम पद की शपथ दिलाई। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं।

इससे पहले आज दोपहर में बीएनपी के सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना था। वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वह दो महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे।

रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई है। इनमें एक हिंदू मंत्री नितार्थी रॉय चौधरी और एक बौद्ध मंत्री दिरेपेन देवान चक्रमा भी शामिल हैं। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं। सभी 24 राज्य मंत्री नए हैं।

उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने तारिक रहमान को भारत आने का न्योता दिया।

पिछले गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 299 में से 209 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया था। इसके अलावा 3 सीटों पर उसकी सहयोगी पार्टियों ने जीत हासिल की।



ओम बिरला ने तारिक रहमान से मुलाकात की

भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्होंने नई सरकार बनने पर भारत की ओर से शुभकामनाएं दीं। यह मुलाकात ढाका में नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद हुई। बैठक के दौरान ओम बिरला ने तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण दिया।

भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने बताया कि दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि भारत और बांग्लादेश मिलकर आम लोगों के हित में काम करेंगे। मुलाकात में दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही, जिससे दोनों देशों के लोगों को सीधा फायदा मिले और रिश्ते और मजबूत हों।

सविधान बदलाव को लेकर सियासी टकराव तेज

इस बीच सविधान में बदलाव को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। दरअसल, 12 फरवरी को संसद चुनाव के साथ 'जुलाई चार्टर' पर जनमत संग्रह भी हुआ था। इसमें 62% लोगों ने 'हां' में वोट दिया। जुलाई चार्टर के मुताबिक नई संसद 180 दिनों के लिए सविधान सभा की तरह काम करेगी। इस अवधि के दौरान सविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में बदलाव किए जाते।

जुलाई चार्टर का मकसद देश में ताकत का एकाधिकार खत्म करना और संतुलन बनाना है। इससे प्रधानमंत्री की ताकत घट जाती और राष्ट्रपति को अधिकार दिए जाते। बीएनपी ने जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन उसके नेता कई प्रावधानों पर आपत्ति जता रहे हैं। पार्टी का कहना है कि चार्टर तैयार करते समय उनसे सलाह नहीं ली गई थी।

विधानसभा घेरने निकले कांग्रेस नेताओं पर बरसाई लाटियां

पुलिस ने पानी की बौछार की; अमीन पटान बोले- कार्यकर्ताओं को चोट आई



बढ़ता राजस्थान

जयपुर। विधानसभा घेराव करने निकले कांग्रेस नेताओं पर पुलिस ने पानी की बौछार की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्का भी हुई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को वॉटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल, राजस्थान कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता 22 गोदाम स्थित सहकार भवन पर इकट्ठा हुए थे। यहां से रैली के रूप में निकले, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पटान ने कहा- प्रदर्शन में 12 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चोट आई है। पुलिस ने आज बर्बरता पूर्वक हम पर वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर लाटियां बरसाईं। हम डरने वाले नहीं हैं। पुलिस गोलियां चलाएगी तो भी हम युवाओं की आवाज को उठाते रहेंगे। इससे पहले 22 गोदाम पर सभा के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल रहे। मंच पर डोटासरा ने गमछा लहराकर डांस भी किया।

अमीन पटान बोले- सरकार को जवाब देना होगा

इस दौरान प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पटान ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे और सरकार को जवाब देना होगा।

पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, वॉटर कैनन चलाई

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज दोपहर डेढ़ बजे जैसे ही विधानसभा की ओर बढ़ने का प्रयास किया, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक हुई। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को तितर-बितर किया।

अमीन पटान बोले- बीजेपी सरकार के गठन के बाद खेल बजट में कमी

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खेलकूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अमीन पटान ने कहा- प्रदेश में बीजेपी सरकार के गठन के बाद खेल बजट में कमी, खिलाड़ियों को समय पर टीए-डीए, प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। खेल मैदानों पर अतिक्रमण और स्टेडियम निर्माण कार्य ठप हो गए हैं, जिससे युवा नशे की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर सरकार ने जल्द से जल्द हमारी वाजिब मांगों को पूरा नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने विधानसभा अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर भाजपा सरकार पर खेल विरोधी नीतियों को समाप्त कर खिलाड़ियों को सुविधाएं और नौकरी देने की मांग की है।

बीजेपी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती

खेल प्रकोष्ठ के प्रदर्शन में गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई सीनियर कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। मंच से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गमछा लहराकर डांस भी किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधकर कहा- विधानसभा गोहत्या के मुद्दे के चलते स्थगित है। बीजेपी को गोमाला से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है।

जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे विषय उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि अमीन पटान के नेतृत्व में यह विंग सभी प्रकोष्ठों में नंबर-वन पर काम कर रहा है।

चांदी 8 हजार गिरी, 2.33 लाख पर आई : सोना 2 हजार घटकर 1.51 लाख हुआ; 4 दिन में चांदी 33 हजार, सोना 6 हजार सस्ता

बढ़ता राजस्थान

नई दिल्ली (एजेंसी)। चांदी में 17 फरवरी को लगातार चौथे दिन गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, एक किलो चांदी 7,992 रुपए गिरकर 2.33 लाख पर आ गई है। वहीं

10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,242 रुपए सस्ता होकर 1.51 लाख पर आ गया है।

चार दिन में सोना 6 हजार और चांदी 33 हजार रुपए सस्ती हुई है। इसने 29 जनवरी को 3.86 लाख का हाई बनाया था। तब से अब तक चांदी 1.53

बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस

दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्र मुद्रण के लिए संपर्क करें।



उच्च क्वालिटी का कागज एवं स्याही

कलर एवं ब्लैक मुद्रण

किफायती मुद्रण लागत

Printing Press

• Hameedpura Road Khandwa, Newai, Tonk, Rajasthan - 304021

Office

• Badhata Rajasthan, Near Rajkiya Mahavidhyalaya, NH-12, Bypass Newai, Tonk, Rajasthan - 304021

(M) +91-9214048888, Phone No. - 01438-223201, 02, 03

• 185/116, "Pratiksha", Sector-18, Pratap Nagar, Sangoner, Jaipur - 302033

(M) +91-9414242258, Phone No. - 0141-2796795

Email: badhatarajasthanprintingpress@gmail.com